**कृषि उपज समिति, चम्बा (बालू) जिला चम्बा (हिमाचल प्रदेश) के लेखोंओं
का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.15 से 31.03.18**

भाग-एक

1 प्रस्तावना :-

(क) कृषि उपज समिति, चम्बा हिमाचल प्रदेश के अवधि 1-04-15 से 31-03-18 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योगिकीय उपज विपणन विद्ययेक 2005 की धारा 48.2 के प्रावधानों के दृष्टिगत इस विभाग द्वारा किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिकारी कृषि उपज समिति चम्बा में सचिव एवं आहरण व संवितरण अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे :-

क्रम सं	आहरण एवं वितरण अधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्री भोला सिंह भट्ट	05-09-14 से 31-07-15
2.	श्री रूप लाल चौहान	01-08-15 से 30-06-16
3.	श्री महेन्द्र सिंह (officiating)	01-07-16 से 08-08-16
4.	श्री प्रताप सिंह पठानिया (officiating)	09-08-16 से 02-01-17
5.	श्री भोला सिंह भट्ट	02-01-17 से 07-02-17
6.	श्री महेन्द्र सिंह (officiating)	08-02-18 से 23-04-18

(ग) आय व व्यय के मुख्य साधन :-

विपणन समिति चम्बा की आय का मुख्य स्रोत, हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योगिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 44 व हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योगिकीय उपज विपणन (साधारण)नियम, 2006 के नियम 35 के अंतर्गत मण्डी समिति के पंजीकृत व्यापारियों से मण्डी शुल्क तथा धारा 75 के अन्तर्गत व्यापारियों से जुर्माना शुल्क, दुकानों का किराया, फार्म विक्रय से प्राप्त आय, जमा राशियों पर अर्जित ब्याज इत्यादि है। इसके अतिरिक्त मण्डी समिति द्वारा मुख्यतः स्थापना, निर्माण कार्य, कार्यालय पर व्यय, गाड़ी के रख-रखाव पर व्यय, प्रशिक्षण शिविरों इत्यादि पर व्यय किया जाता है। उपरोक्त के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योगिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 49(3) के अन्तर्गत कृषि उपज मण्डी समिति के अधिनियम की धारा 44 के अन्तर्गत एकत्रित मण्डी शुल्क का 25 % भाग हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि उपज विपणन बोर्ड को भेजा जाता है।

(घ) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्रम सं०	पैरा सं०	विवरण	रूलाखों में
1	5(ख)	सावधि जमा योजना पर बैंक द्वारा कम ब्याज क्रेडिट करने बारे ।	1.51
2	6	निक्षेप कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना ।	13.41
3	7(क)	दुकानों के किराये की बकाया राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना ।	3.54
4	7(ख)	श्री पवन कुमार नरयाल से दण्ड राशि की वसूली न करना और न ही दुकान खाली करवाने हेतु कार्यवाही करना ।	3.30
5	8	जमानत राशि का अनियमित रूप से अधिक भुगतान करना ।	0.07
6	9	अतिरिक्त आयकर के रूप में अनुचित भुगतान	0.54
7	10	श्री मोहिन्द्र सिंह, सुपरवाइजर द्वारा अग्रिम राशि का समायोजन न करवाना ।	0.54

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

कृषि उपज मण्डी समिति , चम्बा के गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में लम्बित पैरों का विवरण परिशिष्ट "क" पर दिया गया है ।

भाम् दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

कृषि उपज समिति चम्बा के अवधि 1-04-15 से 31-03-18 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण ,जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिए गए है ,श्री मुकेश कुमार खेही,सहायक नियन्त्रक व श्री प्रीतम चन्द,कनिष्ठ लेखा परीक्षक, द्वारा दिनांक 25-07-18 से 21-08-17 तक के दौरान कृषि उपज समिति चम्बा (बालू) स्थित कार्यालय में किया गया । आय के लिए माह 07/15, 03/17 व 09/17 तथा व्यय के लिए माह 12/15,06/16 व 09/17 का चयन विस्तृत जाँच हेतु किया गया ।

वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन को मण्डी समिति के नियन्त्रण अधिकारी/सचिव द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है अंकेक्षण की जिम्मेवारी केवल चयनित माह तक सीमित है ।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

कृषि उपज विपणन समिति चम्बा के अवधि 04/15 से 03/18 तक के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹125497 आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग-शिमला-9 को भेजने हेतु, अनुभाग अधिकारी की अधियाचना संख्या 224 दिनांक 08-08-18 द्वारा वर्तमान सचिव से अनुरोध किया गया व विपणन समिति चम्बा के कार्यालय द्वारा तुरन्त कार्यवाही करते हुए उक्त राशि रेखांकित बैंक ड्राफ्ट सं: 420174 दिनांक 16-08-18 के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दी गई है।

4 वित्तीय स्थिति:-

कृषि उपज मण्डी समिति चम्बा की अवधि 04/15 से 03/18 तक की वित्तीय स्थिति का ब्यौरा निम्न प्रकार से रहा। विस्तृत विवरण परिशिष्ट -ख-1 में दिया गया है।

क्रम सं०	विवरण	2015-16	2016-17	2017-18
1.	आरम्भिक शेष	24249741	25869706	28689124
2.	प्राप्ति/आय	8046278	8457684	7974284
3.	अनुदान	114000	250000	--
4.	ब्याज	2078659	1512835	1855526
5.	जोड़	34488678	36090225	38518934
6.	व्यय	8618972	7401101	9079347
7.	अन्त शेष	25869706	28689124	29439587

अन्तशेष का विवरण :-

(i) दिनांक 31-03-18 को बैंक पास बुक के अनुसार अन्तिम शेष का विवरण निम्न प्रकार से है
परिशिष्ट-ख-2:-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता न०	राशि
1.	एस०बी०आई० परेल	11505735248	719275
2.	एस०बी०आई० नेनीखड	11594627432	139328
3.	स्टेट कोपरेटिव बैंक सरोल	19710100173	1965850
4.	स्टेट कोपरेटिव बैंक चम्बा	17910104528	8103
5.	आई.सी.आई.सी.आई बैंक चम्बा	199201000196	529082
6.	सावधि जमा	परिशिष्ट-ग	24698331
7.	विभिन्न किरायेदारो से प्राप्त प्रतिभूति राशियाँ जो की सावधि जमा के रूप में मार्किट कमेटी के पास जमा थी (परिशिष्ट -ख -3)		80000
8.			कुल जोड़ 28139969

(ii) रोकड़ बही के अन्तशेष व विभिन्न बैंक खातों में जमा राशि में मिलान :-

रोकड़ बही के अन्तशेष तथा बैंक खातों के अन्तशेष का मिलान करके अपेक्षित विवरण परिशिष्ट “ख-4” पर दिया गया है।

4.1 रोकड़ बही व बैंक खातों से पूर्ण मिलान न करना:-

कृषि उपज मण्डी समिति की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि “परिशिष्ट-ख-4” के अनुसार रोकड़ बही व बैंक खातों का पूर्ण मिलान नहीं किया गया था है रोकड़ बही व बैंक खातों में जमा राशि में दिनांक 31-03-18 को ₹512 का अन्तर पाया गया है अतः रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अतिशीघ्र इस अन्तर का मिलान किया जाए व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

4.2 मंडी समिति की धन राशि को कोपरेटिव बैंक के स्थान पर निजी बैंक में जमा करने बारे :-

जाँच में पाया गया कि मण्डी समिति द्वारा परिशिष्ट-ख-2 के अनुसार मण्डी समिति की निधि को आई0 सी0 आई0 सी0 बैंक चम्बा में जमा किया गया है जो कि वित्त विभाग के पत्र सं :फिन-आई०एफ़०(ए)1-68/91 दिनांक 17-04-14 में दिए निर्देशों की सरासर अवेहलना है उक्त पत्र में वर्णित निर्देशों के अनुसार सरकारी संस्थानों की अतिरिक्त राशि कोपरेटिव बैंक में निवेशित की जानी अपेक्षित थी अतः मण्डी निधि की राशि को निजी बैंक में रखने का औचित्य स्पष्ट करें एवं उक्त पत्र के निर्देशों के अनुसार कोपरेटिव बैंक की नजदीकी शाखा में मण्डी निधि को निवेशित करना सुनिश्चित किया जाए।

5 निवेश :-

(क) कृषि उपज मण्डी समिति, चम्बा द्वारा उपलब्ध करवाये गये विवरण के अनुसार दिनांक 31-03-18 तक सावधि जमा योजना में ₹24698331 निवेशित है, जिसका विवरण परिशिष्ट “ग” पर दिया गया है।

(ख) बैंक द्वारा सावधि जमा योजना पर ₹1.51 लाख कम ब्याज क्रेडिट करने बारे :-

सावधि जमा योजना से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि कुछ एक प्रकरणों में बैंक द्वारा सावधि जमा की राशियों पर कम ब्याज क्रेडिट दिया गया जिसका विवरण निम्नप्रकार से है :-

दिनांक	सावधि सं/बैंक	राशि	दर	अवधि	अपेक्षित ब्याज	प्राप्त ब्याज	कम प्राप्त ब्याज
05-04-15	32929162303-SBI	4636147	9%	1 साल	431548	387608	43940
15-05-15	31172120901-SBI	2645957	9%	1 साल	246294	224165	22129
05-04-17	32929162303-SBI	5464079	8.5%	1 साल	407047	366340	40707
15-05-17	31172120901-SBI	3103733	7.25%	1 साल	231213	208090	23123

12-01-18	32137599169/SBI	1280428	8.5%	1 साल	367507	346682	20825
					कुल कम प्राप्त ब्याज		150724

अतः देय ब्याज से कम क्रेडिट दिए गए ब्याज की सम्बन्धित बैंको से वसूली हेतु समुचित पग उठाए जाए व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

6 ₹13.41लाख के निक्षेप कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

वर्तमान अंकेक्षण अवधि 04/15 से 03/18 के दौरान कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु मार्किटिंग बोर्ड व अन्य विभागों के पास डिपाजिट वर्क के रूप में ₹1340646 जमा करवाए गए परन्तु इनसे सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :-

(क) 2015 -16

क्रम संख्या	कार्य का नाम	ड्राफ्ट सं व दिनांक	राशि
1.	P/L tiles flooring in farmer rest house on 1 st floor existing 6 no shops .	Through RTGS	169000
2.	c/o matting & tarring campond area approach road at R.M market yard baloo	----do----	500000
3.	c/o collection centre at mehla	----do----	146954
4.	c/o collection centre at sei	----do----	123972
		जोड़	939926

(ख) 2016-17

क्रम संख्या	कार्य का नाम	ड्राफ्ट सं व दिनांक	राशि
1.	Renovation of chairman & retiring room at mrket yard baloo	Rtgs	179862
2.	c/o approach road civil supply godown salooni	Rtgs	163508
3.	Repair of water work at office at baloo	Rtgs	57350
		जोड़	400720
		कुल जोड़ (क+ख)	1340646

ऑडिट अधियाचना सं: 225 दिनांक 08-08-18 द्वारा उक्त कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्रों को सम्बन्धित विभाग से प्राप्त करने हेतु सचिव, मण्डी समिति को अवगत करवाया गया व सचिव मण्डी समिति के पत्र सं: 212 दिनांक 08-08-18 द्वारा ऑडिट को अवगत करवाया गया कि उपयोगिता प्रमाण पत्रों हेतु हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड शिमला को पत्र लिखें है जैसे ही उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होंगे ऑडिट को अवगत करवा दिए जायेंगे। अतः उक्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों को सम्बन्धित विभागों से शीघ्र प्राप्त कर इस विभाग को अवगत करवाना सुनिश्चित किया।

7 दुकानों के किराये की बकाया राशि ₹3.54 लाख वसूली हेतु शेष तथा इनसे सम्बन्धित अन्य अनियमितताएं :-

(क) दुकानों के किराये की बकाया राशि ₹3.54 लाख वसूली हेतु शेष:-

विपणन समिति की चम्बा बालू स्थित सब्जी मण्डी में निर्मित 12 दुकानों के किराये से सम्बन्धित मांग एवं वसूली रजिस्टर के अनुसार किरायेदारों से दिनांक 31-03-18 तक निम्न विवरणानुसार किराये की ₹353514/- वसूली हेतु शेष पाई गई। जिससे स्पष्ट होता है कि कृषि उपज समिति, चम्बा किराये की उगाही हेतु गम्भीर नहीं है। अतः निम्न विवरणानुसार लम्बित राशियों की वसूली हेतु तुरन्त यथोचित पग उठाये जाए ताकि समिति की आय की उगाही में कोताही न हो तथा वसूली न होने के कारण ब्याज के रूप में होने वाली हानि से भी बचा जा सके। अनियमितता का यह प्रकरण प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, शिमला-2 के विशेष ध्यानार्थ भी आवश्यक एवं उचित कार्यवाई हेतु लाया जाता है।

अवधि	गत शेष	वर्ष की मांग	कुल योग	वर्ष की वसूली	बकाया राशि
2015-16	362349	350640	712989	378359	334630
2016-17	334630	362174	696804	361096	335708
2017-18	335708	379538	715246	361732	353514

दिनांक 31-03-18 तक उपरोक्त वसूली योग्य राशि का सम्बन्धित किरायेदार के अनुसार विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम सं	दुकानदार का नाम	दुकान न०	प्रतिमाह किराया	वसूली हेतु शेष राशि
1.	श्री राकेश कुमार	7 (पुराना)	1660	21318
2.	श्री कुलदीप कुकरेजा	9 (पुराना)	1660	97112
3.	श्री शिव नाथ	11 (पुराना)	1660	82904
4.	श्री अमित महाजन	12 (पुराना)	1660	48133
5.	श्री मानव विशाल	13 (पुराना)	1660	78163
6.	श्री अनिल कुमार	6 (पुराना)	1408	25884
7.			कुल जोड़	353514

क्रम सं 1 से 5 पर वर्णित दुकानदार दिनांक 30-04-11 को अपनी दुकानों को खाली कर चुके हैं तथा इन दुकानदारों से बकाया किराये की राशि की वसूली हेतु मामला तहसीलदार (रिकवरी) के अधीन लम्बित है

(ख) श्री पवन कुमार नरयाल पुत्र श्री सरदारी लाल को अनुचित लाभ पहुंचाते हुए दण्ड राशि ₹3.30 लाख की वसूली न करना और न ही दुकान खाली करवाने हेतु कार्रवाई करना :-

श्री पवन कुमार नरयाल को किराये पर आबंटित दुकान न० 5 का आबंटन उनके द्वारा हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योगिकीय उपज विपणन विद्ययेक 2005 के अंतर्गत आबंटन की शर्तों के अनुसार काम न करने के कारण तथा दिनांक 16-04-11 को समिति की बैठक में लिए गए निर्णय की अनुपालना में सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति चम्बा (हिमाचल प्रदेश) के पत्र सं :कृउमस-चम्बा(आबंटन)2010-11/485-493.दिनांक 18-04-11 द्वारा दिनांक 1-05-11 से रद्द कर दिया गया तथा दिनांक 30-04-11 के दुकान का कब्जा वापिस सौंप देने के आदेश दिए अन्यथा दो से पांच गुणा तक किराये की वसूली दण्ड स्वरूप करने तथा जमा प्रतिभूति को जब्त किए जाने के आदेश दिए गए थे। जाँच में पाया गया कि श्री पवन कुमार नरयाल द्वारा आबंटन रद्द करने के आदेशों की अवहेलना करते हुए अपनी दुकान खाली नहीं की गई और न ही कब्जा मण्डी समिति को सौंपा गया। मण्डी समिति द्वारा उपरोक्त पत्र जारी करने के उपरांत श्री पवन कुमार नरयाल से न तो दुकान वापिस लेने हेतु और न ही दण्ड की वसूली हेतु कोई ठोस कार्रवाई की गई यद्यपि श्री पवन नरयाल द्वारा चैक सं 344645 दिनांक 30-09-12 द्वारा मण्डी समिति के पास ₹20360 जमा करवाई गई थी, परन्तु यह चैक Dishonour हो गया था फिर भी मण्डी समिति द्वारा उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस प्रकार खाते में पैसा न होते हुए चैक का देना (चैक का Dishonour होना) एक अपराधिक कृत्य है जिस हेतु उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही का किया जाना अपेक्षित था, परन्तु मार्किट कमेटी द्वारा उनको अनुचित लाभ पहुंचाते हुए उनके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई और न ही राशि की वसूली की गई, जिसके कारण स्पष्ट किए जाए। तत्पश्चात आबंटन रद्द करने के 3 वर्ष 8 माह बाद अत्यन्त विलम्ब से दिनांक 27-12-14 को सचिव मण्डी समिति द्वारा पत्र सं : ए०पी०एम०सी०चम्बा(अन्य) 2014-15/593 द्वारा श्री पवन नरयाल को दुकान खाली करने तथा 5 गुणा किराया दण्ड स्वरूप कार्यालय में 3 दिन में जमा करवाने के आदेश दिए गए, परन्तु पवन नरयाल द्वारा फिर भी आदेशों की अनुपालना नहीं की गई। नस्ति की जाँच में यह पाया गया कि दिसम्बर 2014 के पश्चात से वर्तमान समय तक लगभग 34 माह व्यतीत हो जाने पर भी मण्डी समिति द्वारा श्री पवन नरयाल के विरुद्ध दुकान खाली करवाने व दण्ड राशि को वसूलने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई जोकि पांच गुणा किराये के साथ माह 5/11 से 08/18 तक ₹330000 (₹3750x88) (प्रति माह किराया ₹750 व 5 गुणा ₹3750) बनती है। उक्त मामला गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 6 (ख) द्वारा मण्डी समिति व उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया गया था परन्तु इतनी अवधि व्यतीत होने उपरांत मण्डी समिति प्रशासन द्वारा श्री पवन नरयाल को अनुचित लाभ पहुंचाते हुए उक्त

पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जो की एक अतिगंभीर मामला है। अंकेक्षण अधियाचना सं 235 दिनांक 20-08-18 द्वारा मण्डी समिति को अवगत करवाया परन्तु कोई उत्तर नहीं दिया गया अतः यह मामला पुनः प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य विपणन बोर्ड के विशेष ध्यान में इस आशय से लाया जाता है कि इस सन्दर्भ में मण्डी समिति को अविलम्ब उचित कार्रवाई अमल में लाने हेतु दिशा निर्देश जारी किए जाएँ तथा उनके द्वारा की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को भी अवगत करवाया जाए।

(ग) मण्डी समिति की सब्जी मण्डी में दुकान न० 1,7,8 दिनांक 01-05-11 से व 11 न० दिनांक 01-04-15 से खाली पड़ी है, परन्तु मण्डी समिति द्वारा इन्हें किराये पर देने हेतु कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए हैं। अतः परामर्श दिया जाता है कि इन्हें किराये पर चढाने हेतु प्रयास किए जाएँ ताकि मण्डी समिति को किराये के रूप में अधिक आय प्राप्त हो सके।

8. जमानत राशियों का अनियमित रूप से वापिस करने के परिणामस्वरूप ₹0.07 लाख का अधिक भुगतान करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार दुकानदारों को उनके द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशियों का पूर्ण भुगतान किया गया जबकि हिमाचल प्रदेश कृषि उपज उप नियम 2007 के नियम 62 (2)XXXii के अनुसार यदि दुकानदार द्वारा दुकान/गोदाम को खाली करने पर उनके द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि का 50% भाग ही वापिस करना अपेक्षित था परन्तु मण्डी समिति द्वारा उक्त नियम की अवेहलना करते हुए निम्न दुकानदारों को पूर्ण राशि का भुगतान किया गया, परिणामस्वरूप ₹7500/- का अधिक भुगतान किया गया। अंकेक्षण अधियाचना सं 226 दिनांक 08-08-18 द्वारा इन भुगतानों को करने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु कहा गया परन्तु मण्डी समिति कार्यालय द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया जो की एक गंभीर मामला है अतः ₹7500/- की वसूली सम्बन्धित से की जाए व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए व भविष्य में इस प्रकार के भुगतान नियमानुसार करना सुनिश्चित किया जाए।

फर्म का नाम	माह जिसमें भुगतान किया गया	एफडीआर न.	वसूली जमानत राशि	भुगतान योग्य जमानत राशि	अधिक भुगतान
मै० हरीश ग़ोवर दुकान न,6	03/16	PFQ426428PNB	5000	2500	2500
मै० सूरज प्रकाश शर्मा दुकान न० 11	04/16	31354520914SBI	10000	5000	5000
				कुल अधिक भुगतान	7500

9 मण्डी समिति प्रशासन द्वारा आयकर आयुक्त के समक्ष अपना पक्ष न रखने के कारण आयकर के रूप में ₹0.54 लाख का अनुचित भुगतान करने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि मण्डी समिति द्वारा वाउचर सं 148 दिनांक 1-12-16 द्वारा निम्न विवरणानुसार आयकर आयुक्त को अतिरिक्त आयकर के रूप में ₹54245/- का भुगतान किया गया है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा सं 7 के अनुसार भी वाउचर सं 210 दिनांक 27-03-14 द्वारा ₹612910 अतिरिक्त आयकर की राशि का भुगतान किया जा चुका था। इस प्रकार मार्केट कमेटी प्रशासन द्वारा प्रबन्ध निदेशक से पूर्व स्वीकृति प्राप्त न करना व इस सन्दर्भ में कोई कार्यवाही न करना मण्डी समिति प्रशासन की लापरवाही व चूक को परिलक्षित करता है। अतः यह मामला प्रबन्ध निदेशक मण्डी बोर्ड व उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में लाया जाता है कि इस प्रकरण में पूर्ण छानबीन करके वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा मण्डी समिति द्वारा भुगतान की गई अतिरिक्त आयकर की प्रतिपूर्ति हेतु प्रभावी कदम उठाए जा सके तथा की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को भी अवगत करवाया जाए।

वर्ष	चालान न.	दिनांक	आयकर की अतिरिक्त राशि
2004-05	22	03-12-16	18929
2005-06	23	यथोपरि	14344
2007-08	21	यथोपरि	20972
		कुल जोड़	54245

10 श्री मोहिन्द्र सिंह ,मण्डी पर्यवेक्षक द्वारा आहरित ₹0.54 लाख की अग्रिम राशि को समायोजित न करवाने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि वाउचर सं 195 माह 12/15 द्वारा श्री मोहिन्द्र सिंह ,मण्डी पर्यवेक्षक को ₹54000/- की अग्रिम राशि किसान प्रशिक्षण कैंप के आयोजन हेतु जारी की गई थी परन्तु वर्तमान अवधि तक उक्त अग्रिम राशि को सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा समायोजित नहीं किया गया जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 2009 के नियम 189(3) के अनुसार आहरित अग्रिम राशि को 15 दिनों के अन्दर समायोजित करवाना अपेक्षित था। ऑडिट अधियाचना सं 219 दिनांक 04-08-18 द्वारा उक्त कैंप कब, कहाँ करवाया व उक्त अग्रिम राशि को समायोजित न करवाने बारे औचित्य स्पष्ट करने हेतु मण्डी समिति से कहा गया परन्तु मण्डी समिति द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया जोकि एक गंभीर मामला है। ऑडिट को ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त राशि का दुरुपयोग किया गया है जिसके लिए स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा उक्त अग्रिम राशि को सम्बन्धित से वसूल कर मण्डी निधि में जमा किया जाए व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

11 जलपान हेतु अध्यक्ष मण्डी समिति को अनुचित रूप से ₹0.02 लाख का भुगतान करने बारे :-

वाउचर सं 184 माह 12/15 की जाँच करने पर पाया गया कि जलपान हेतु ₹2000/- का भुगतान अध्यक्ष मण्डी समिति को किया गया जबकि इसका बिल दिनांक 30-11-15 को प्रस्तुत किया था तथा नियमानुसार इसका भुगतान कैंटीन को दिया जाना था जबकि इसका भुगतान अध्यक्ष मण्डी समिति को किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

12 बिजली बिल के साथ किए अधिभार के भुगतान बारे:-

वाउचर सं 194 माह 12/15 की जाँच करने पर पाया गया कि ₹7731 का भुगतान हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम कार्यालय को विद्युत बिल के भुगतान किया गया। जाँच में पाया गया कि इस बिल का समय पर भुगतान न करने के कारण अधिभार के रूप में ₹144 का भी भुगतान किया गया जिसके कारण स्पष्ट किए जाएँ अन्यथा इस राशि की प्रतिपूर्ति उचित स्रोत से की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 पंजीकृत व्यापारियों द्वारा मंडी शुल्क के समर्थक में प्रस्तुत 'ओ' फार्म पर वस्तु की किस्म प्रमात्रा/वजन, दर इत्यादि न दर्शाने बारे

परिशिष्ट "घ" में वर्णित व्यापारियों के 'ओ' फार्म की जाँच करने पर पाया गया कि इन व्यापारियों द्वारा 'ओ' फार्म में वस्तु की किस्म, प्रमात्रा/वजन व दर इत्यादि पूर्ण विवरण नहीं दर्शाया गया है। जबकि ओ फार्म में सभी कालम विहित है। इस प्रकरण में मण्डी समिति के किसी भी प्राधिकारी/कर्मचारी द्वारा इस आशय की पुष्टि नहीं की गई है कि इस अवधि में विना किस्म, प्रमात्रा/वजन व दर दर्शाया गया व्यापार वास्तविक तथ्यों पर आधारित है अथवा नहीं? मण्डी समिति द्वारा ओ फार्म विना पूर्ण विवरण के स्वीकृत किए जा रहे हैं। इस प्रकार वसूले गए मण्डी शुल्क की प्रमाणिकता तथा वैधता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। उक्त से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि मण्डी समिति कार्यालय द्वारा आय एकत्रीकरण हेतु किसी प्रभावशाली नियन्त्रण एवम पर्यवेक्षण के स्थान पर व्यापारियों द्वारा 'ओ' फार्म में दर्शाए गए कुल मूल्य आधार पर मण्डी शुल्क वसूला जा रहा है, जोकि उचित प्रक्रिया नहीं है। अतः 'ओ' फार्मों को विना पूर्ण विवरण दिए मंडी शुल्क की वसूली करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सम्बन्धित प्रभारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए भविष्य में व्यापारियों से 'ओ' फार्म पूर्ण विवरण सहित वसूल करवाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

14 बिना क्यू फार्म के मण्डी फीस वसूलने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान मण्डी यार्ड बालू के व्यापारियों की पंजिकाओं की जाँच करने पर पाया गया कि मण्डी समिति द्वारा मण्डी यार्ड के व्यापारियों की फीस की वसूली बिना क्यू फार्म के की जा रही है जबकि प्रबन्ध निदेशक विपणन बोर्ड के पत्र सं HMB (F)2/-27/2013-3824 दिनांक

31-07-14 के अनुसार मण्डी यार्ड के व्यापारियों की फीस ओ फार्म व क्यू फार्म के आधार पर वसूलना अपेक्षित है जबकि केवल ओ फार्म के आधार पर की जा रही है जो की अनियमित है अंकेक्षण अधियाचना सं 234 दिनांक 20-08-18 द्वारा सचिव मण्डी समिति को स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया परन्तु कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः बिना क्यू फार्म के आधार पर फीस वसूलने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

15 विभिन्न व्यापारियों से मण्डी शुल्क को देय तिथि पर न वसूलने के कारण मण्डी समिति को ब्याज के रूप में सम्भावित हानि का होना :-

मण्डी समिति के पंजीकृत व्यापारियों के 'ओ' फार्म की जाँच करने पर पाया गया कि मण्डी समिति द्वारा मण्डी शुल्क की वसूली नियमानुसार करने की अपेक्षा अत्यन्त विलम्ब से की जा रही है और मण्डी समिति के पंजीकृत व्यापारियों द्वारा कई-कई महीने का मण्डी शुल्क एक साथ जमा करवाया गया है जबकि हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योगिकीय उपज विपणन विद्ययेक 2005 की धारा 45.2 के अनुसार मण्डी फीस को 14 दिन के अन्दर वसूलना अपेक्षित है जैसा कि परिशिष्ट "ड." में दिए गए विवरणों से स्पष्ट होता है कि कुछ व्यापारियों से मण्डी शुल्क की वसूली 6 माह से अधिक समय के पश्चात की गई है। इस प्रकार विलम्ब से वसूली गई मण्डी शुल्क से अप्रत्यक्ष रूप से ब्याज की हानि हुई है। यदि यथासमय पर मण्डी शुल्क वसूला गया होता तो संलिप्त राशियों पर बैंक से ब्याज के रूप में मण्डी समिति को अधिक आय प्राप्त हो सकती थी। भविष्य में मण्डी शुल्क की वसूली नियमानुसार समय पर की जाए तथा विलम्ब की स्थिति में समस्त संलिप्त मामलों में यथा प्रावधानानुसार दण्ड शुल्क सहित ही मण्डी शुल्क की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से यथाशीघ्र अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

16 (क) गाड़ी न० HP-73-0773 से मंडी समिति के अधिक्षेत्र से बाहर की गई यात्रा की पूर्व अनुमति प्राप्त न करना :-

गाड़ी नं० HP-73-0773 की लाग बुक की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार 7444 किलोमीटर की यात्रा मंडी समिति के अधिक्षेत्र से बाहर की गई, जिसकी अनुमति, प्रबन्ध निदेशक, विपणन बोर्ड शिमला से प्राप्त नहीं की गई है जबकि प्रबन्ध निदेशक विपणन बोर्ड शिमला के पत्र सं: एच०एम०बी०(ओ०एस०)(2)-13/06-2250 दिनांक 07-03-07 के पैरा-2 अनुसार कार्यालय वाहन को मण्डी समिति के अधिसूचित क्षेत्र बाहर ले जाने से पूर्ण प्रबन्ध निदेशक से अनुमति लेना आवश्यक था। अतः निम्न यात्राओं की प्रबन्ध निदेशक से पूर्ण अनुमति न लेने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा निम्न यात्राओं को निजी यात्रा मानते हुए इसकी सम्बन्धित से वसूली की जाए व की गई कार्यवाही से ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

अवधि	किलोमीटर	यात्रा का विवरण
20-07-15 से 23-07-15	930	बालू से शिमला व वापिस वाया बददी, ऊना
06-11-15 से 08-11-15	775	बालू से शिमला व वापिस वाया परवाणु, ऊना

07-02-15 से 09-02-16	860	बालू से शिमला व वापिस
11-04-16 से 13-04-16	860	बालू से शिमला व वापिस
03-08-16 से 05-08-16	1072	बालू से शिमला व वापिस वाया ऊना
02-02-17 से 04-02-17	1004	बालू से शिमला व वापिस वाया बददी, चंडीगढ़
19-06-17 से 21-06-17	990	बालू से शिमला व वापिस वाया ऊना ,तलवाडा
19-07-17 से 21-07-17	953	बालू से शिमला व वापिस
कुल जोड़	7444	किलोमीटर

(ख) उक्त वाहन की लाग बुक की जाँच करने पर पाया गया कि गाड़ी की औसत प्रत्येक माह 8 किलोमीटर से 8.30 किलोमीटर प्रति लीटर तक की दर्शाई गई है ,परन्तु गाड़ी की औसत का निर्धारण किसी तकनीकी अधिकारी से नहीं करवाया गया है। अतः गाड़ी द्वारा दर्शाई जा रही तेल की खपत को उचित ठहराने हेतु अविलम्ब हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग अथवा हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के तकनीकी अधिकारी से गाड़ी की औसत का निर्धारण करवाया जाए। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा सं 20(क) में भी इस बारे ऑडिट द्वारा आपत्ति उठाई गई थी परन्तु मण्डी समिति द्वारा इस बारे कोई कार्यवाही नहीं की गई। जो की एक गम्भीर मामला है अतः गाड़ी की औसत का निर्धारण उचित संस्था से करवा कर ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

17 फार्म-ओ ,आर तथा क्यू इत्यादि का स्टॉक व विक्रय रजिस्टर प्रस्तुत न करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान उपरोक्त फार्मों का स्टॉक रजिस्टर व उनके विक्रय से सम्बन्धित रजिस्टर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके आभाव में उक्त फार्मों के गत शेष,प्राप्ति ,बिक्री व बिक्री उपरांत अन्त शेष की जाँच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना सं 236 दिनांक 20-08-18 द्वारा सचिव मण्डी समिति को अवगत करवाया परन्तु कोई उत्तर नहीं दिया गया अतः उक्त रजिस्ट्रों को प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

18 (क) सेवा पुस्तिका में अर्जित अवकाश का शेष अधिक दर्शाने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं की जाँच करने पर पाया कि दिनांक 30-06-18 को गलत गणना करने पर अर्जित अवकाश का शेष अधिक दर्शाया गया जो की उचित नहीं है अतः इन सेवा पुस्तिकाओं में अर्जित अवकाश के शेष को ठीक करके सही शेष दर्शाया जाए व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए।

कर्मचारी का नाम	पद का नाम	सेवा पुस्तिका में दर्शाया शेष	ऑडिट द्वारा गणना करने पर शेष	अधिक शेष
श्री मोहिन्द्र सिंह	सुपरवाइजर	315	314	1
श्री संजय कुमार	ड्राईवर	66	65	1
नगीना बेगम	चपड़ासी एवं चौकीदार	73	72	1

(ख) श्री योग राज,चपड़ासी एवं चौकीदार को अनियमित रूप से अर्धवेतन अवकाश स्वीकृत करने के परिणास्वरूप वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान :-

श्री योग राज चपड़ासी की सेवा पुस्तिका की जाँच करने पर पाया गया कि कर्मचारी को अनुचित रूप से बार-बार अर्धवेतनिक अवकाश स्वीकृत किया गया जबकि उक्त कर्मचारी के खाते में अर्धवेतन अवकाश शेष नहीं था। ऑडिट द्वारा गणना करने पर पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार दिनांक 30-06-18 को उक्त कर्मचारी को 83 दिन का अर्ध वेतन अनियमित रूप से स्वीकृत किया गया जिसके लिए स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा 83 दिनों के वेतन व भतों की वसूली सम्बन्धित से की जाए तदनुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत किया जाए :-

***जबकि मण्डी समिति द्वारा 30-06-18 को परिणित अवकाश के खाते में शून्य दर्शाया है।**

क्रम सं०	विवरण	अथ शेष	स्वीकृत अर्ध वेतन अवकाश	अनियमित रूप से स्वीकृत अर्धवेतन अवकाश	अन्तशेष
1	दिनांक 01-01-16 को उक्त कर्मचारी के खाते में शेष अर्ध वेतन अवकाश	-	-	-	17
2	दिनांक 08-5-16 से 19-06-16 तक स्वीकृत 86 दिन का अर्धवेतन अवकाश	17	86	69	शून्य
3	दिनांक 01-07-16 को जमा अर्ध वेतन अवकाश 10 दिन	10	-	-	10
4	दिनांक 01-01-17 को जमा अर्ध वेतन अवकाश 10 दिन	20 (10+10)	-	-	20
5	दिनांक 20-03-17 से 05-04-17 तक स्वीकृत 34 दिन का अर्धवेतन अवकाश	20	34	14	शून्य
6	दिनांक 01-07-17 को जमा अर्धवेतन अवकाश 10 दिन	10	-	-	10
7	दिनांक 01-01-18 को जमा अर्धवेतन अवकाश 10 दिन	20 (10+10)	-	-	20
8	दिनांक 29-01-18 से 02-02-18 तक स्वीकृत 10 दिन का अर्धवेतन अवकाश	20	10	-	10
	अनियमित रूप से स्वीकृत अर्धवेतन अवकाश			83	

नोट:- दिनांक 30.6.18 को अर्धवेतन अवकाश खाते में अन्तशेष शून्य दर्शाया गया जबकि वास्तव में 10 दिन शेष था।

19 मार्किट फीस के निर्धारण (असैसमेंट) न करने बारे :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या : 227 दिनांक :- 08-08-18 द्वारा सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति चम्बा से अंकेक्षण अवधि की मंडी शुल्क की असैसमेंट से सम्बन्धित अभिलेख आवश्यक जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत करवाने हेतु अनुरोध किया गया परन्तु सम्बन्धित प्रभारी द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया कि अंकेक्षण अवधि की असैसमेंट नहीं की गई है जबकि हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योगिकिय उपज विपणन विधयेक 2005 की धारा 61 के अनुसार वार्षिक आधार पर मंडी शुल्क की असैसमेंट की जानी अपेक्षित थी । अतः नियमानुसार मंडी शुल्क की असैसमेंट न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए ।

20 लघु-आपत्ति विवरणिका :- यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है ।

21 निष्कर्ष :- लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरिक्षण की आवश्यकता है ।

हस्ता / -

(ज्ञान चन्द शर्मा)

उप निदेशक

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009

फोन नं0-0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल0ए0) एच(2) सी (15)(14)45/90 खण्ड-3-260-262 दिनांक,

9.1.19 शिमला-9

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

- 1 विशेष सचिव (कृषि) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002
- 2 प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खलीनी, शिमला-171002
- पंजीकृत: 3 सचिव, कृषि उपज विपणन समिति चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।

हस्ता / -

(ज्ञान चन्द शर्मा)

उप निदेशक

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009

फोन नं0-0177-2620881

**कृषि उपज मण्डी समिति ,चम्बा(बालू) जिला चम्बा
पैरा 1 (ड.) में वर्णित परिशिष्ट "क"**

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

कृषि उपज मण्डी समिति,चम्बा के अवधि 4/2002 से 3/15 तक के 5 अंकेक्षण प्रतिवेदनों के कुल 58 पैरे लम्बित थे। शेष लम्बित पैरों में उठाई गई आपत्तियों के अनुसार मण्डी शुल्क के रूप में वसूली, ठेकेदारों को किए गए अनियमित भुगतानों, दुकानों के किराये, व अन्य मामलों में उजागर की गई वसूलियों की वसूली करना शामिल है। अतः अंकेक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से अंकेक्षण द्वारा उजागर करने के बावजूद ऐसी गम्भीर अनियमितताओं पर विभाग द्वारा प्रभावी ढंग से कार्यवाई न करना बहुत बड़ी लापरवाही है जिसके परिणामस्वरूप मण्डी समिति को भारी वित्तीय हानि उठानी पड सकती है क्योंकि लम्बी समय अवधि बीत जाने के कारण इन वसूलियों को प्रभावित करना मुश्किल होगा। अतः वित्तीय अनियमितताओं एवं वसूलियों से सम्बन्धित सभी पैरों के निपटारे हेतु प्रभावी ढंग से कार्यवाई करनी अति आवश्यक है जिसके लिए तुरन्त कार्यवाई करनी सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना की सूचना समय-2 पर इस कार्यालय को भेजी जाये। शेष बचे ऑडिट पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :-

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2002 से 03/2004 :-

क्रम सं	पैरा सं	पैरे की स्थिति	टिप्पणी
1.	9	अनिर्णीत	----

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2004 से 03/2007 :-

क्रम सं	पैरा सं	पैरे की स्थिति	टिप्पणी
1.	8	अनिर्णीत	----
2.	9	अनिर्णीत	----
3.	11	अनिर्णीत	----
4.	12	आंशिक अनिर्णीत	----
5.	13	अनिर्णीत	----
6.	16	अनिर्णीत	----

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2007 से 03/2009 :-

क्रम सं	पैरा सं	पैरे की स्थिति	टिप्पणी
1	12	अनिर्णीत	----
2.	14	अनिर्णीत	----

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2009 से 03/2011 :-

क्रम सं	पैरा सं	पैरे की स्थिति	टिप्पणी
1.	9	अनिर्णीत	----
2.	12	अनिर्णीत	----
3.	14	अनिर्णीत	----
4.	15	अनिर्णीत	----

(ड) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2011से 03/2015 :-

क्रम सं	पैरा सं	पैरे की स्थिति	टिप्पणी
1	5(क)	निर्णीत	कार्यवाही देख ली गई है।
2	5(ख)	अनिर्णीत	----
3	5(ग)	निर्णीत	रसीद सं 467309 दिनांक 20-08-18 द्वारा वसूली कर ली गई है।
4	5(घ)	निर्णीत	कार्यवाही देख ली गई है।
5	6(क)	निर्णीत	पैरे को पुनःप्रारूपित किया गया।
6	6(ख)	निर्णीत	पैरे को पुनःप्रारूपित किया गया।
7	6(ग)	आंशिक निर्णीत	-----
8	6(घ)	निर्णीत	पैरे को पुनःप्रारूपित किया गया।
9.	7	अनिर्णीत	-----
10.	8	अनिर्णीत	-----
11.	9(क)	अनिर्णीत	-----
12.	9(ख)	अनिर्णीत	-----
13.	9(ग)	निर्णीत	रसीद सं 467312,13 दिनांक 21-08-18 द्वारा 3923 की वसूली कर ली गई है।
14.	9(घ)	निर्णीत	रसीद सं 467314 दिनांक 21-08-18 द्वारा 273 की वसूली कर ली गई है।
15.	9(ड.)	अनिर्णीत	-----
16.	9(च)	अनिर्णीत	-----
17.	9(छ)	अनिर्णीत	-----
18.	10(क)	आंशिक निर्णीत	-----
19.	10(ख)	निर्णीत	कार्यवाही देख ली गई है।
20.	10(ग)	अनिर्णीत	-----
21.	10(घ)	निर्णीत	कार्यवाही देख ली गई है।
22.	11(क)	अनिर्णीत	----
23.	11(ख)	अनिर्णीत	----
24.	11(ग)	अनिर्णीत	----
25.	12	निर्णीत	कार्यवाही देख ली गई है।
26.	13	अनिर्णीत	----
27.	14	अनिर्णीत	----
28.	15(क)	अनिर्णीत	----
29.	15(ख)	अनिर्णीत	----

30.	16(क)	निर्णीत	रसीद सं 467310 दिनांक 21-08-18 द्वारा 177 की वसूली कर ली गई है।
31.	16(ख)	अनिर्णीत	----
32.	17(क)	निर्णीत	कार्यवाही देख ली गई है।
33.	17(ख)	निर्णीत	कार्यवाही देख ली गई है।
34.	17(ग)	अनिर्णीत	----
35.	18(क)	अनिर्णीत	----
36.	18(ख)	अनिर्णीत	----
37.	18(ग)	निर्णीत	रसीद सं 467311 दिनांक 21-08-18 द्वारा 680 की वसूली कर ली गई है।
38.	19(क)	निर्णीत	कार्यवाही देख ली गई है।
39.	19(ख)	निर्णीत	कार्यवाही देख ली गई है।
40.	19(ग)	निर्णीत	कार्यवाही देख ली गई है।
41.	20(क)	अनिर्णीत	----
42.	20(ख)	अनिर्णीत	----
43.	20(ग)	अनिर्णीत	----
44.	21(क)	निर्णीत	अग्रिम वाउचर सं 92 दिनांक 01-08-15 द्वारा समायोजित कर दिया गया था।
45.	21(ख)	निर्णीत	अग्रिम वाउचर सं 123 दिनांक 09-10-11 द्वारा समायोजित कर दिया गया था।
46.	21(ग)	निर्णीत	कार्यवाही देख ली गई है।

अनिर्णीत पैरों का सार	पैरों की संख्या
गत अंकेक्षण प्रतिवेदनो के अनुसार अनिर्णीत पैरे	59
वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंकेक्षण प्रतिवेदन में लगाए गए पैरे	(+) 17
कुल पैरे	76
अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे	21
अन्त शेष (दिनांक 31-3-18 तक)	55